मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

रांची, दिनांक: 30/09/2021

मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति-496/2021

30 सितंबर 2021

मंत्रालय

==========

★ मुख्यमंत्री ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

==========

★ बिना अनापत्ति वाले दाखिल खारिज के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए

★ *राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन हो

==========

रांची

मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की । इसके तहत दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि सीमांकन के मामले, राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में लंबित मामले, भू अर्जन के लिए मुआवजा की स्थिति और विभिन्न विभागों को जमीन हस्तांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई ।

ई कोर्ट की मॉनिटरिंग हो

इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एल खियांगते ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों में मामलों की रेगुलर सुनवाई नहीं हो रही है और और ना ही लंबित मामलों का निष्पादन हो रहा है । यह काफी चिंता की बात है ।मुख्यमंत्री ने कहा

कि उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य राजस्व पदाधिकारियों के ई कोर्ट की रेगुलर मीटिंग की जाए । साथ ही न्यायालय में लंबित मामलों का लिस्ट तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन करें ।

बैंकों में मुआवजे की लगभग 12 सौ करोड़ रुपए पड़े हुए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना अनापत्ति वाले दाखिल कार्य के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए । इस मौके पर विभाग के अपर सचिव में उद्योगों के लिए लैंड बैंक बनाने के लिए उठाए गए कदमों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।उन्होंने कहा कि भू अर्जन से संबंधित मामलों में भी मुआवजे का वितरण सही तरीके से होना सुनिश्चित करें । बैंकों में मुआवजे की लगभग 12 सौ करोड़ रुपए पड़े हुए हैं । भूमि अधिग्रहण नहीं होने से कई बड़े परियोजनाओं को चालू करने में अड़चने आ रही हैं। सभी जिले के उपायुक्त भू अर्जन से जुड़े मामलों में लाभार्थियों के बीच मुआवजा का वितरण करने के लिए तेजी से कदम उठाएं।

###

==========

#Team PRD(CMO)